इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2066
जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है।
22 माघ, 1947 (शक)

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार

2066. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विस्तार से विशेषतः कमजोर आबादी को बाहर न किया जाए, निगरानी का जोखिम या आंकड़ों का दुरुपयोग न हो;
(ख) वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनरुद्धार के आलोक में प्रचालनात्मक फैब, समय-सीमा और स्वदेशी क्षमता के संबंध में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत क्या ठोस प्रगति हुई है; और
(ग) सरकार बार-बार इंटरनेट बंद होने से भारत की वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं और संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने पूरे भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को बढ़ावा दिया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने खुले, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल प्लेटफार्मों के माध्यम से जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल सेवाओं के वितरण को सक्षम करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) दृष्टिकोण अपनाया है।

सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान के लिए (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर और एपीआई सेतु) आदि के लिए जनसंख्या पैमाने पर मूलभूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को सफलतापूर्वक लागू किया है। डीपीआई भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति रहा है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन, शासन प्रणाली और आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि करता है।
डिजिटल बहिष्करण को रोकने के लिए, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहल में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) – भाषिनी के माध्यम से बहुभाषी इंटरफेस, विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच सुविधाएं, और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और अन्य सुविधा चैनलों के माध्यम से सहायता प्राप्त सेवा वितरण शामिल है, जिससे ग्रामीण और कमजोर आबादी के लिए अंतिम छोर तक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का विस्तार समावेशी, सुरक्षित और कमजोर आबादी सहित नागरिकों की गोपनीयता और अधिकारों का सम्मान करता रहे। निम्नलिखित कानूनी और नीतिगत सुरक्षा उपाय मौजूद हैं:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को इस तरह से संसाधित करने के लिए एक व्यापक कानूनी तंत्र प्रदान करता है जो ऐसे डेटा के वैध उपयोग को सक्षम करते हुए अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है।

- डीपीडीपी अधिनियम बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें माता-पिता या वैध अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति की आवश्यकता शामिल है।
- आधार तंत्र आधार अधिनियम, 2016 द्वारा शासित है और संबंधित नियम पहचान डेटा के स्टोरेज, एक्सेस और शेयरिंग पर सख्त नियंत्रण लगाते हैं।

सेमीकंडक्टर विकास कार्यनीति माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस कार्यनीति के भाग के रूप में, भारत का लक्ष्य डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

अर्थव्यवस्था के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग की मूलभूत प्रकृति को देखते हुए, सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 'सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम' शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य उपलब्धियां/प्रगति निम्नलिखित हैं:

- सरकार ने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के परिकल्पित निवेश के साथ 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जिसमें 2 फैब और 8 पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं। इन इकाइयों में अन्य बातों के साथ-साथ कॉम्प्लिमेंट्री मेटल-ऑक्साइड- सेमीकंडक्टर **(**सीएमओएस) (सिलिकॉन) फैब, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, उन्नत पैकेजिंग, मेमोरी पैकेजिंग आदि शामिल हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 4 इकाइयों में पायलट उत्पादन शुरू हो गया है।
- स्टार्टअप्स के माध्यम से 24 चिप डिजाइन परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया गया है। 16 ने टेप आउट पूरा कर लिया है और 13 को वेंचर कैपिटल फंडिंग प्राप्त हुई है।
- 350 विश्वविद्यालयों को 65,000 इंजीनियरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरणों तक पहुंच प्रदान की गई है।

बजट 2026-27 में सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अधिसूचित दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी को इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश जारी करने से पहले सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सभी उचित विकल्पों का पता लगाना चाहिए। यदि इस तरह के निलंबन को आवश्यक समझा जाता है, तो निलंबन आदेश को स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए प्रकाशित किया जाना चाहिए और परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र और निर्दिष्ट अवधि तक सीमित होना चाहिए।

आम तौर पर, किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन के दौरान, केवल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया जाता है और वॉयस कॉलिंग और शॉर्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) जैसी अन्य दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के लोग संचार कर सकते हैं और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।

ये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता भारत की वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं और संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ संतुलित है।

*****